शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 48 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 48 अंक – 29 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 17 – 24 जुलाई 2023 मूल्य पांच रूपए

विक्रमादित्य सिंह की अफसरशाही को चेतावनी सरकार में संभावित विस्फोट का पहला संकेत

➢ केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर प्रदेश के लिए तीन हजार करोड़ का प्रबंध एक बड़ी उपलब्धि

➢ सरकार में हर उपेक्षित की आवाज बनने की ओर है यह पहला कदम

➢ किसी दण्डित कर्मचारी नेता के हमलों से यह कदम नहीं रुकेंगे

➢ सरकार को अपनी कार्यप्रणाली सुधारने का भी पहला संकेत है ब्यान

शिमला/शैल। सुक्खू सरकार के पदभार संभालने के बाद मुख्यमंत्री ने सत्ता संचालन के सूत्र के रूप में प्रदेश की जनता से यह कहा था कि वह राज करने नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन करने आये हैं। इस आठ माह में व्यवस्था परिवर्तन के प्रयोग से जो अवस्था शासन-प्रशासन में उभर कर आयी है उसके परिणाम स्वरूप आज सुक्खू के मंत्री अपने में ही आमने सामने खड़े होने के कगार पर पहुंच गये हैं। शिमला टैक्सी यूनियन विवाद में पहली बार मंत्री आपस में उलझे। उसके बाद अवैध खनन पर मंत्री टकराव में आये। सेब ढुलाई के मामले में तो बागवानी मंत्री और मुख्यमंत्री के ही अलग-अलग स्टैंड सामने आ गये हैं। अब लोक निर्माण मंत्री को तो पत्रकार वार्ता के माध्यम से यह कहने की नौबत आ गयी की अधिकारी अपनी सीमा न लांघें। पार्टी अध्यक्षा को तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से यह कहना पड़ गया है कि वह अपने को आहत और उपेक्षित महसूस कर रही हैं। यह सब कुछ प्रदेश की जनता के सामने खुलकर आ चुका है क्योंकि व्यवहारिक सच यही है। नेता प्रतिपक्ष से लेकर नीचे तक सारा विपक्ष इस पर तंज कर रहा है। इस तरह सरकार की जो तस्वीर आम आदमी में बनती जा रही है उसको सामने रखते हुये यह नहीं लगता कि आने वाले लोकसभा चुनावों में प्रदेश की चारों सीटों पर कब्जा कर पायेगी। हाईकमान के पास भी एक सर्वे के माध्यम से यह स्थिति पहुंच चुकी है। यदि समय रहते हालात पर नियन्त्रण न पाया गया तो इससे राष्ट्रीय स्तर पर भी पार्टी के लिये स्थितियां कठिन हो सकती हैं।

ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि अब तक जो घटा है उस पर कुछ विस्तार से चर्चा की जाये। स्मरणीय है कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों के दौरान प्रदेश की जनता को दस गारंटीयां जारी की थी। यह गारंटीयां जारी करते हुये यह नहीं कहा गया था कि इन्हें अगले विधानसभा चुनाव के चुनावी वर्ष में लागू किया जायेगा। बल्कि इन गारंटीयों पर लोकसभा चुनावों में जनता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से जवाब मांगेगी। क्योंकि गांव में यह सवाल कार्यकर्ता से ही पूछे जायेंगे। वहां पर बड़ा नेता तो उपलब्ध नहीं रहता है। मंत्रियों में जो यह आमने-सामने की स्थितियां बनती जा रही है इस पर सवाल पूछे जायेंगे। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आज कांग्रेस का कार्यकर्ता ही अपने को हताश और उपेक्षित महसूस कर रहा है। क्योंकि ब्लॉक और जिला स्तर पर वही प्रशासनिक व्यवस्था बैठी हुई हैं जो भाजपा शासन के दौरान वहां पर थी और उसी के खिलाफ आम कार्यकर्ता का गुस्सा था रोष था। व्यवस्था के नाम पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यह लग ही नहीं रहा है कि सरकार बदल गयी है। क्योंकि सरकार बदलने के बाद दो माह के भीतर ब्लॉक जिला और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण और प्लानिंग कमेटीयां गठित होती थी जिनमें पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सदस्य नामित किया जाता था और इस तरह करीब दो हजार कार्यकर्ता अपने को सम्मानित महसूस करते थे। सरकार की सहायता के लिये एक समानान्तर व्यवस्था खड़ी हो जाती थी। विभिन्न निगमों/बोर्डो में संचालन मण्डल गठित किये जाते थे। इन कदमों से संगठन मजबूत होता था। सरकार बनने के बाद संगठन को मजबूती प्रदान करना सरकार का दायित्व होता है। लेकिन सरकार ने इस दिशा में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। कार्यकर्ता जब संगठन के पदाधिकारियों से इस बारे में कोई बात उठाते हैं तो यही निष्कर्ष निकलता है कि सरकार जानबूझकर संगठन को कमजोर कर रही है।

भाजपा शासन में जनता महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त थी। इसी से सत्ता परिवर्तन हुआ था। जनता को यह आशा थी कि उसे महंगाई और बेरोजगारी से राहत मिलेगी। लेकिन इन आठ माह में इन दोनों मुहानों पर जनता को घोर निराशा ही अब तक मिली है। क्योंकि बिजली पानी और राशन हर चीज के दामों में बढ़ौतरी की गयी है। दो बार तो डीजल के रेट बढ़ाये गये हैं जिसका असर हर चीज पर हुआ है क्योंकि ट्रक यूनियनों ने इसके कारण माल भाड़े के रेट बढ़ा दिये हैं। युवाओं को रोजगार देने के मामले में भी यह सरकार कुछ नहीं कर पायी है। बेरोजगार युवा सरकार के खिलाफ लामबन्द होता जा रहा है। सरकार के आते ही एक लाख युवाओं को रोजगार देने की गारंटी दी गयी थी। लेकिन रोजगार देने के बजाये उस अदारे को ही बन्द कर दिया गया जिसके माध्यम से रोजगार मिलता था। लोक सेवा आयोग को यह अतिरिक्त काम सौंपा गया है और इससे उसका काम भी प्रभावित हो गया है। क्योंकि वहां पर कोई नये संसाधन इस काम के लिये नहीं दिये गये हैं। जबकि वहां पर सदस्य का एक पद खाली चला आ रहा है जिसे भरकर आयोग के संसाधन बढ़ाये जा सकते थे। आम आदमी की भी यही शिकायत है कि उसके काम नहीं हो रहे हैं। अभी स्थानान्तरणों को लेकर महीने के अंतिम चार दिनों में ही विचार किये जाने की जो नीति घोषित की गयी है उस पर विधायक रवि ठाकुर ने ही खुलेआम नाराजगी व्यक्त कर दी है।

इस समय आम आदमी सरकार से संतुष्ट नहीं है उसे लग रहा है की गारंटीयां देकर उससे छल किया गया है। सरकार नाजुक वित्तीय स्थिति के नाम कीमतें बढ़ाने के अतिरिक्त संसाधन जुटाने का और कोई व्यवहारिक उपाय कर नहीं रही है। कीमतें इस तरह से बढ़ाई जा रही है कि लोग जल्द ही इसे भूल जायेंगे। इस आपदा में भी सरकार राहत राशि बढ़ाने की घोषणाएं तो करती जा रही हैं लेकिन व्यवहारिक रूप से पीड़ित तक यह सहायता पहुंचने में लम्बा समय लगेगा। ऐसे हालात में जब मंत्रियों/ विधायकों के लिये भी यह स्थिति आ जाये कि अफसरशाही इन्हें भी हल्के से लेना शुरू कर दें तो स्थिति निश्चित रूप से विस्फोटक होने के कगार पर पहुंच चुकी है। यह विक्रमादित्य की पत्रकार वार्ता से स्पष्ट हो गया है। विक्रमादित्य सिंह का अफसरशाही को यह कहना कि वह लक्ष्मण रेखा न लांघें और इसे बर्दाश्त नहीं किया जायेगा अपने में बहुत कुछ संकेत दे जाता है। विक्रमादित्य सिंह ने दिल्ली जाकर केंद्रीय मंत्रियों के सामने जिस तरह से पक्ष रखा है उससे प्रदेश के लिये उन्होंने तीन हजार करोड़ का प्रबंध करके अपनी सूझबूझ और कार्यकुशलता का परिचय दे दिया है। उनके कदमों को किसी दण्डित कर्मचारी नेता के ब्यानों के माध्यम से रोकना संभव नहीं होगा। इस पत्रकार वार्ता के बाद संगठन और सरकार में हर उस व्यक्ति की उम्मीद और आवाज बन जायेंगे जो इस वातावरण में अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं।

राज्यपाल ने किया अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले का शुभारम्भ

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश का गौरवशाली इतिहास और परम्पराएं राज्य की प्रगति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं और उन्हें भावी पीढ़ी के लिए भी संरक्षित किया जाना चाहिए। प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित होने वाले मेले समृद्ध संस्कृति के संरक्षण एवं प्रसार में श्रेष्ठ भूमिका निभाते हैं। यह बात राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने चम्बा जिला में ऐतिहासिक मिंजर मेले के शुभारम्भ अवसर पर बतौर मुख्यातिथि कही। राज्यपाल बनने के पश्चात शिव प्रताप शुक्ल का यह चम्बा जिला का पहला दौरा था। इस अवसर पर लेडी

गवर्नर जानकी शुक्ल उनके साथ उपस्थित रहीं।

उन्होंने प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय मिंजर महोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि चंबा जिला अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध संस्कृति के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर गांव और शहर की एक भिन्न सांस्कृतिक पहचान है, जो अन्यत्र नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि मेलों के माध्यम से संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करके आपसी भाईचारे की भावना को बढ़ावा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि मिंजर महोत्सव का प्राचीन परंपराओं, मान्यताओं और आस्थाओं से गहरा संबंध है।

इससे पूर्व, राज्यपाल ने पारंपरिक कुंजड़ी मल्हार गीतों के बीच मिंजर ध्वज फहराकर मेले का औपचारिक शुभारम्भ किया। उन्होंने प्राचीन लक्ष्मीनारायण मंदिर में मिंजर भेंट कर आशीर्वाद लिया।

उन्होंने कला एवं शिल्प मेले तथा विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा वर्तमान सरकार की उपलब्धियों को दर्शाती प्रदर्शनी का भी शुभारम्भ किया।

इस अवसर पर राज्यपाल ने मिंजर मेला खेल प्रतियोगिताओं की औपचारिक शुरुआत की।

राज्यपाल ने चम्बा में केन्द्रीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने चम्बा में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ जिले में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने रेडक्रॉस, प्रधानमंत्री टी.बी. मुक्त भारत अभियान की गतिविधियों की समीक्षा करने के साथ-साथ ही जिला में भारी बारिश के

कारण हुई क्षति के उपरान्त राहत कार्यो का भी जायजा लिया।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि ज़िला चम्बा प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण है तथा यहां की कला एवं संस्कृति भी बहुत समृद्ध है। ऐतिहासिक महत्व का जिला होने के बावजूद नीति आयोग ने इसे 'अकांक्षी जिला' की श्रेणी में शामिल किया है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि जिला के प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन जब अधिक समर्पण भाव से करेंगे, तभी वह आकांक्षी जिला की सूचि से बाहर आ सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक योजना के शुभारम्भ अवसर पर बतौर मुख्यातिथि कही। राज्यपाल बनने के पश्चात शिव प्रताप शुक्ल का यह चम्बा जिला का पहला दौरा था। इस अवसर पर लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल उनके साथ उपस्थित रहीं।

उन्होंने प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय मिंजर महोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि चंबा जिला अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध संस्कृति के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर गांव और शहर की एक भिन्न सांस्कृतिक पहचान है, जो अन्यत्र नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि मेलों के माध्यम से संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करके आपसी भाईचारे की भावना को बढ़ावा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि मिंजर महोत्सव का प्राचीन परंपराओं, मान्यताओं और आस्थाओं से गहरा संबंध है।

इससे पूर्व, राज्यपाल ने पारंपरिक कुंजड़ी मल्हार गीतों के बीच मिंजर ध्वज फहराकर मेले का औपचारिक शुभारम्भ किया। उन्होंने प्राचीन लक्ष्मीनारायण मंदिर में मिंजर भेंट कर आशीर्वाद लिया।

उन्होंने कला एवं शिल्प मेले तथा विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा वर्तमान सरकार की उपलब्धियों को दर्शाती प्रदर्शनी का भी शुभारम्भ किया।

इस अवसर पर राज्यपाल ने मिंजर मेला खेल प्रतियोगिताओं की औपचारिक शुरुआत की।

के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई गई है, जिससे जिला में कार्यो की प्रगति नज़र आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विभाग अपने काम का आकलन करें और अधिकारी फील्ड में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

राज्यपाल ने कहा कि जिले में सड़क नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए वैकल्पिक योजना पर कार्य की एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने उपायुक्त को विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से सड़क संबंधी रिपोर्ट तैयार करने के उपरांत उन्हें उपलब्ध करवाने को कहा। वह इस रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय मंत्री से अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवाने के लिए बात करेंगे। उन्होंने कहा कि जिला में पर्यटन क्षेत्र को और अधिक विस्तार देने के लिए जिले में मजबूत सड़क नेटवर्क का होना बहुत जरूरी है।

राज्यपाल ने कहा कि जिले में 756 क्षय रोगी तथा 156 निक्षय मित्र हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से अधिक से अधिक लोगों को निक्षय मित्र बनाने को कहा। इसके अलावा उन्होंने नशे के खिलाफ बड़ा अभियान चलाने को भी कहा।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि वह जिले में विकास गतिविधियों को गति देना सुनिश्चित कर रहे हैं और राज्यपाल के मार्गदर्शन से उन्हें लाभ मिलेगा। उन्होंने राज्यपाल से भूमिहीनों को पुनर्वास के लिए वन भूमि उपलब्ध कराने का मामला उठाने का भी आग्रह किया।

इस अवसर पर विधायक नीरज नैय्यर और डी.एस. ठाकुर ने भी अपने बहुमूल्य सुझाव दिये।

उपायुक्त अपूर्व देवगन ने जिले में विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों और केंद्रीय योजनाओं की प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव संदीप कदम और पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव भी उपस्थित थे।

इससे पहले राज्यपाल ने जिला रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर का भी शुभारम्भ किया और रक्तदाताओं को सम्मानित किया। उन्होंने टीबी रोगियों को स्वास्थ्य किट भी वितरित किये।

राज्यपाल ने भूरी सिंह संग्रहालय का भी दौरा किया। उन्होंने पदमश्री ललिता वकील और विजय शर्मा को जिला की समृद्ध कला और संस्कृति के संरक्षण में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित भी किया गया।

नौणी विवि में वाइन मेकिंग कोर्स के लिए प्रवेश आरम्भ

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के लोग डॉ यशवंत सिंह परमार औदयानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी में वाइन मेकिंग के व्यावसायिक पाठयक्रम में दाखिला ले सकेंगे। विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए अपने व्यावसायिक पाठयक्रम के लिए इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह पहली बार है जब विश्वविद्यालय यह कार्यक्रम चलाएगा। वोकेशनल कोर्स की अवधि 12 सप्ताह होगी।

इस पाठयक्रम का मुख्य फोकस वाइन प्रौद्योगिकी के बुनियादी अवधारणाओं के साथ-साथ व्यावहारिक पहलुओं पर होगा। प्रतिभागियों को पैकेजिंग, मैच्योरिटी, मिश्रण और गुणवत्ता पहलुओं सहित वाइन के उत्पादन के लिए सभी इकाई संचालन से भी परिचित करवाया जाएगा।

इस डिप्लोमा कार्यक्रम के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कम से कम 40 प्रतिशत के साथ कक्षा 10+2 या समकक्ष है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 अगस्त है और काउंसलिंग 9 अगस्त को आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम में कुल 10 सीटें उपलब्ध हैं। विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.yspuniversity.ac.in से आवेदन पत्र डाउनलोड किया जा सकता है।

भरा हुआ आवेदन पत्र साथ कक्षा 10, कक्षा 10+2/स्नातक प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रतियों, स्कूल के प्रमुख या किसी राजपत्रित अधिकारी या संबंधित ग्राम पंचायत प्रधान से चरित्र प्रमाण पत्र, 100 रुपये के बैंक ड्राफ्ट को प्रोफेसर और विभाग अध्यक्ष, खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, डॉ. वाई.एस. परमार औदयानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी-सोलन (हिमाचल प्रदेश)-173230 को रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजना होगा। आवेदन पत्र नियत तिथि तक विभाग में जमा किया जा सकता हैं।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: त्रटचा शर्मा

राज्यपाल ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री से भेंट की

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की।

उन्होंने उन्हें राज्य में भारी बारिश और बादल फटने से हुए नुकसान से अवगत करवाया।

राज्यपाल ने प्रधानमंत्री को राज्य सरकार और एन.डी.आर.एफ. द्वारा संचालित किए जा रहे राहत और बचाव कार्यो के बारे में जानकारी दी तथा राज्य को सहायता राशि जारी करने और अर्द्धसैनिक बलों व एन.डी.आर.एफ. को तैनात करने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया।

राज्यपाल ने प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री को अवगत करवाया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मंडी और सोलन जिलों में प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति की समीक्षा की है।

प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री ने राज्यपाल को हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।

राज्यपाल ने साइकलिस्ट आशा मालवीय को सम्मानित किया

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राजभवन में साइकलिस्ट

आशा मालवीय को सम्मानित किया जो साईकल पर भारत भ्रमण कर रही हैं। राज्यपाल ने उन्हें इस अभियान की सफलता के लिए शुभकामनाएं दीं।

राज्यपाल ने उनके प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उनका यह अभियान महिला सशक्तिकरण तथा सुरक्षा के उद्देश्य से आरम्भ किया गया है।

आशा मालवीय मध्यप्रदेश से संबंध रखती हैं तथा उन्होंने एक खिलाड़ी तथा पर्वतारोही के रूप में अपनी विशेष पहचान बनाई है। उनकी यह साईकल यात्रा मध्यप्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर 01 नवम्बर, 2022 को भोपाल से आरम्भ हुई थी तथा इसका समापन स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में होगा। इस अभियान के दौरान वह देश के 28 राज्यों में कुल 25 हजार किलोमीटर की दूरी तय करेंगी। अभी तक उन्होंने 24 राज्यों में 20 हजार किलोमीटर की दूरी तय कर ली है तथा हिमाचल उनकी यात्रा का 25वां प्रदेश है।

ग्राम पंचायतों के अंग्रेज़ी व हिन्दी नामों पर आपत्तियां आमंत्रित

शिमला/शैल। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में ग्राम पंचायतों के नाम अंग्रेजी व हिंदी भाषा में प्रमाणित करने की प्रक्रिया आरंभ की गई है।

उन्होंने बताया कि भारत सरकार के Local Govt.Directory नामक सॉफ्टवेयर तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न सॉफ्टवेयरज़ और सरकारी योजनाओं में ग्राम पंचायतों के हिन्दी तथा अग्रेज़ी भाषा में प्रामाणिक, शुद्ध तथा एक समान नामों को प्रयोग में लाने की दृष्टि से प्रदेश की समस्त 3615 ग्राम पंचायतों के नामों की हिन्दी व अंग्रेज़ी भाषा में ज़िलावार सूची स्थानीय जनता के आक्षेपों के लिए प्रकाशित की गई है। यह सूची विभागीय वेबसाइट www.hppanchayat.nic.in तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के ई-राजपत्र में स्थानीय लोगों के अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत के हिन्दी व अग्रेज़ी नामों में त्रुटियों, यदि कोई हो, के बारे में अपनी आपत्ति सम्बन्धित उपायुक्त को 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकता है। सम्बन्धित उपायुक्त प्राप्त आपत्तियों पर विचार करके निर्णय लेने के पश्चात ग्राम पंचायत के नामों के अन्तिम प्रकाशन की सिफारिश राज्य सरकार को करेगा। राज्य सरकार द्वारा इन सिफारिशों के दृष्टिगत ग्राम पंचायतों के शुद्ध नामों की अन्तिम अधिसूचना जारी की जाएगी। अन्तिम रूप से अधिसूचित नाम उपयोग के लिए प्रामाणिक होंगें तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न सॉफ्टवेयर्ज़ तथा सरकारी योजना में प्रयोग किये जाएंगे जिससे विभिन्न दस्तावेज़ों में ग्राम पंचायतों के प्रामाणिक, शुद्ध और एक समान नाम उपलब्ध होंगे।

पर्यटन विकास निगम के होटलों में 50 प्रतिशत तक छूट

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के प्रवक्ता ने बताया कि निगम अपने होटलों में कमरों की बुकिंग पर 50 प्रतिशत तक छूट प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह छूट तुरंत प्रभाव से लागू कर दी गई है और 15 सितम्बर, 2023 तक जारी रहेगी।

प्रवक्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जारी भारी बारिश के दृष्टिगत प्रदेश में पर्यटकों को सुलभ आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने तथा निगम के होटलों में अक्युपेंसी बढ़ाने के दृष्टिगत लिया गया है।

पहाड़ी राज्यों को अलग पैटर्न पर आर्थिक सहायता प्रदान करने का आग्रहः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहां राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वित्तीय

सलाहकार रवनीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में आपदा से हुए नुकसान का आकलन करने के लिये आये आठ सदस्यीय केंद्रीय दल के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय दल को अवगत करवाया कि प्रदेश में भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ के कारण भारी नुकसान हुआ है, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार को हिमाचल की उदारता से मदद करनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार को वर्ष 2013 में केदारनाथ में आयी आपदा के दौरान मिली सहायता की तर्ज पर हिमाचल को भी केन्द्र सरकार की ओर से आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के आपदा से संबंधित वर्तमान दिशा-निर्देशों में बहुत कम आर्थिक सहायता का प्रावधान है। प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और निर्माण इत्यादि की अधिक लागत को देखते केंद्र सरकार को हिमाचल सहित अन्य पहाड़ी राज्यों को अलग पैटर्न पर आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भारी बारिश और बाढ़ के कारण प्रदेश में बिजली, पानी और सड़क परियोजनाओं को बड़े पैमाने पर क्षति पहुंची है, जिसे स्थाई रूप से बहाल करने में काफी वक्त लगेगा और विशेष आर्थिक सहायता की भी आवश्यकता होगी। ऐसे में इस त्रासदी से उबरने के लिए प्रदेश को उदार वित्तीय मदद के लिए केन्द्र सरकार को आगे आना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अन्तरिम राहत के लिए केन्द्र सरकार को पत्र भी लिखा है और मानसून के बाद इस बारे में संशोधित ज्ञापन दिया जाएगा।

बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, वित्त सचिव अक्षय सूद, विशेष सचिव राजस्व डी.सी.राणा, मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव विवेक भाटिया सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

सेब, आलू ढुलाई में लगे बाहरी राज्यों के ट्रकों को विशेष पथ कर से छूटःमुकेश अग्निहोत्री

शिमला/शैल। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि किसानों और बागवानों की सुविधा के लिये राज्य सरकार ने सेब और आलू के सुचारू परिवहन के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने वाले बाहरी राज्यों के ट्रकों को विशेष पथ कर के भुगतान से छूट देने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय परमिट के अंतर्गत नहीं आने वाले ट्रकों को इस वर्ष 20 जुलाई से 31 अक्तूबर तक इस छूट का लाभ मिलेगा।

मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि यह निर्णय किसानों और बागवानों के उत्थान के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इससे सेब व आलू के सीजन में ढुलाई की पर्याप्त परिवहन सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस छूट के परिणामस्वरूप परिवहन लागत में कमी आएगी, जिससे उत्पादकों की आय में भी वृद्धि होगी।

उप-मुख्यमंत्री, जिनके पास परिवहन मंत्री का प्रभार भी है, ने दोहराया कि राज्य सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से कठिन समय में विशेषकर उन बागवानों एवं कृषकों को राहत मिलेगी जो भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ के कारण प्रभावित हुये हैं।

53 स्वास्थ्य संस्थानों में शुरू होगी हॉस्पिटल मैनेजमेंट इनफॉर्मेशन सिस्टम सुविधाःमुख्यमंत्री

शिमला/शैल। राज्य सरकार प्रदेश के सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों, सभी चिकित्सा महाविद्यालयों, क्षेत्रीय अस्पतालों सहित 53 स्वास्थ्य संस्थानों

में हॉस्पिटल मैनेजमेंट इनफॉर्मेशन सिस्टम लागू करने जा रही है, जिसमें रोगियों का पूरा डाटा एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो सकेगा। इससे मरीजों को विभिन्न सुविधाओं सहित उनके बहुमूल्य समय की भी बचत होगी।

यह बात मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुये कही।

मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में एचएमआईएस को 30 अगस्त, 2023 तक शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्यों के अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में यह सुविधा 30 सितम्बर, 2023 तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। इस सुविधा के शुरू होने से डॉक्टरों के पास मरीज का पूरा डाटा उपलब्ध होगा, जिसके माध्यम से रोगियों की सामान्य व इमरजेंसी रजिस्ट्रेशन, लैब रिपोर्ट, ऑपरेशन थियेटर के रिकॉर्ड सहित उनके डिस्चार्ज और ट्रांसफर का पूरा डाटा ऑनलाइन उपलब्ध होगा। इस सुविधा से डॉक्टर ई-प्रिसक्रिप्शन भी लिख सकेंगे और मरीजों की पूरी मेडिकल हिस्ट्री भी देख सकेंगे, जिससे रोगियों के साथ-साथ डॉक्टरों को भी सुविधा होगी।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है तथा इस दिशा में यह सुविधा मील पत्थर सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी स्वास्थ्य संस्थानों में अत्याधुनिक फर्नीचर और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर भी काम कर रही है। राज्य सरकार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधा प्रदान करने की दिशा में भी कदम बढ़ा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य संस्थानों का निर्माण एवं उनमें सुविधाएं भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने भविष्य में निर्मित होने वाले सभी अस्पतालों में प्राइवेट रूम की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन सभी मेडिकल कॉलेजों की समीक्षा भी की तथा इनके निर्माण कार्यो को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिये।

अस्पतालों को विश्व स्तरीय उपकरण उपलब्ध करवाएगा चिकित्सा सेवाएं निगम

शिमला/शैल। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने हिमाचल प्रदेश चिकित्सा सेवाएं निगम की दूसरी बोर्ड बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि निगम द्वारा विश्व स्तरीय खरीद का एक आदर्श मॉडल स्थापित किया जाएगा।

डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, जो निगम के अध्यक्ष भी हैं, ने कहा कि इस निगम के तहत खरीद प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त और प्रतिस्पर्धी होगी। उन्होंने कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से निगम के माध्यम से खरीदी जाने वाली दवाओं और उपकरणों की गुणवत्ता का निरीक्षण करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उच्च गुणवत्ता व मानकों को ध्यान में रखकर खरीद की जा रही है।

उन्होंने कहा कि निगम के तहत खरीद, वित्तीय मंजूरी और निरीक्षण इकाइयां स्थापित की जाएंगी और वे खरीद को मंजूरी प्रदान करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों को प्राथमिकता देंगे।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बैठक में प्रबंध निदेशक और अन्य निदेशकों की नियुक्ति, बैंक खाता खोलने, प्रबंध निदेशक और निगम के अन्य अधिकारियों को वित्तीय शक्तियां सौंपने को भी मंजूरी दी गई।

इस निगम की स्थापना हाल ही में स्वास्थ्य विभाग से संबंधित खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने एवं इसे प्रतिस्पर्धी बनाने के दृष्टिगत की गई है।

आपदा निधि के तहत लम्बित 315.80 करोड़ जारी करने का केन्द्र से आग्रहः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से 315.80 करोड़ रुपये की राशि शीघ्र जारी करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह राशि पिछले कुछ वर्षो से रूकी हुई है जिसमें राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि के तहत वर्ष 2020-21 के लिए आवंटित 121.71 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2021-22 के लिए 133.56 करोड़ रुपये और राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के तहत वर्ष 2019-20 के लिए 61.07 करोड़ रुपये की राशि शामिल है। उन्होंने कहा कि महालेखा परीक्षक की ओर से लगाई गई आपत्तियों के कारण इसमें देरी हुई है और प्रदेश सरकार ने अब इन आपत्तियों का सफलतापूर्वक समाधान कर दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चूंकि अब सभी आपत्तियों का निस्तारण किया जा चुका है, ऐसे में राज्य में हाल ही में भारी बारिश और बाढ़ के कारण हुई क्षति को देखते हुए इस आपदा की स्थिति में यह राशि शीघ्र जारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा के दृष्टिगत उत्पन्न त्वरित आवश्यकताओं को पूर्ण करने के दृष्टिगत राज्य सरकार ने इस आवंटित निधि को शीघ्र जारी करने का आग्रह केन्द्र सरकार से किया है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह राशि अगर शीघ्र जारी होती है तो हाल ही में प्रदेश में आई विपदा से प्रभावितों को राहत पहुंचाने तथा उनके पुनर्वास में इसका सदुपयोग किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आशान्वित है कि उसके आग्रह पर केन्द्र शीघ्र कार्यवाही करते हुए इस चुनौतीपूर्ण समय में अपना सहयोग एवं समर्थन बनाए रखेगा।

इस बार सेब वजन के हिसाब से बिकेगाः बागवानी मंत्री

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार सेब उत्पादकों के कल्याण तथा आगामी सेब सीजन को सफल बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। इस बार सेब बाजार में वजन के हिसाब से बेचने का निर्णय लिया गया है।

यह बात बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने प्रदेश के सेब उत्पादकों, आढ़तियों तथा सेब व्यापार के अन्य हितधारकों के साथ आयोजित बैठक में कही। बैठक के दौरान सभी वर्गो से सेब सीजन को सफल बनाने के लिए सुझाव भी लिये गये।

बागवानी मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश अपने सेब के लिए देश-विदेश में प्रसिद्ध है। हिमाचल का सेब जहां अपने स्वाद के लिये जाना जाता है वहीं इसके सह-उत्पादों की भी बाजार में मांग है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने बागवानों के हित को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सल कॉर्टन की बजाये वजन के हिसाब से सेब की बिक्री का निर्णय लिया है। इस निर्णय से बागवानों, आढ़तियों तथा अन्य हितधारकों के अधिकार भी सुरक्षित होंगे।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बैठक के दौरान प्राप्त उचित सुझावों को लागू करने पर विचार करेगी। लेकिन सरकार अपने निर्णय के अनुसार वजन के हिसाब से सेब की बिक्री के मामले में पीछे नहीं हटेगी। प्रदेश के कानून के संबंध में किसी को भी निराधार टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी की जा रही हैं तथा पारदर्शिता बनाये रखने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक के दौरान बागवानों, आढ़तियों, लदानियों तथा अन्य हितधारकों ने सर्वसम्मति से प्रदेश सरकार द्वारा वजन के हिसाब से सेब की बिक्री के निर्णय का स्वागत किया इस पर अपना सहयोग जताया।

इस अवसर पर पूर्व विधायक एवं हिमाचल सेब उत्पादक संघ के अध्यक्ष राकेश सिंघा, पूर्व महापौर शिमला नगर निगम एवं संयुक्त किसान मंच के सह-संयोजक संजय चौहान, निदेशक बागवानी विभाग संदीप कदम, हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम के महाप्रबन्धक हितेश आजाद, हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड के प्रबन्ध निदेशक हेमिस नेगी, सचिव कृषि उत्पादन विपणन समिति देवराज कश्यप तथा संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न किसान, बागवान, आढ़ती तथा व्यापारी संघों के प्रतिनिधि भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

विधवा पुनर्विवाह अनुदान योजना राशि बढ़ाने पर कर रही विचार प्रदेश सरकार

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार विधवा पुनर्विवाह अनुदान योजना के अन्तर्गत प्रदान की जा रही अनुदान राशि को 65,000 से रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये करने पर विचार कर रही है। सरकार की इस पहल से विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन मिलने के साथ-साथ उनका पुनर्वास भी सुनिश्चित हो सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव को मंजूरी के लिए शीघ्र ही प्रदेश मंत्रिमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के वंचित वर्गो के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार ने इन वर्गो के सम्मानजनक और सशक्त जीवनयापन के उद्देश्य से नवीन और कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं।

यदि परिस्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नही बिगाड़ सकता।..... स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

मणिपुर क्यों जल रहा है

मणिपुर लम्बे अरसे से जल रहा है। वहां की हिंसा बर्बरता की सारी सीमाएं लांघ गयी है। देश के गृहमंत्री वहां का दौरा कर चुके हैं। लेकिन उनके सारे प्रयास हिंसा को रोक नहीं पाये हैं। जबकि चालीस हजार सैनिक, अर्ध सैनिक और पुलिस बल वहां पर तैनात हैं। प्रधानमंत्री मणिपुर की हिंसा पर मौन रहे हैं। अब जब संसद सत्र शुरू होने पर मणिपुर हिंसा का एक वीडियो वायरल होकर सामने आया जिसमें महिलाओं को निर्वस्त्र करके नंगा घुमाया गया और बलात्कार किया गया तब प्रधानमंत्री की पहली प्रतिक्रिया आयी है। प्रधानमंत्री ने इस घटना को देश को शर्मसार करने वाली घटना करार देकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिये जाने की बात की है। मणिपुर को लेकर संसद हर रोज स्थगित हो रही है। विपक्ष इस पर बहस की मांग कर रहा है तो सत्तापक्ष इसके साथ बंगाल और राजस्थान की घटनाओं को उठा रहा है। ऐसी हिंसा और महिलाओं के साथ ऐसी बर्बरता कहीं भी हो वह निन्दनीय है। जो भी सरकार ऐसे अपराधों पर कारवाई करनें में चूक करे उसे सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। मणिपुर का यह अपराध मई माह में हुआ है। पुलिस की मौजूदगी में हुआ है। लेकिन इसका वीडियो अब संसद सत्र के शुरू होने पर वायरस होकर बाहर आया है।

मणिपुर में हिंसा रूक नहीं रही है या रोकी नहीं जा रही है। इस सवाल की पड़ताल करने के लिये मणिपुर की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को समझना आवश्यक हो जाता है। यहां पर मैंतेई, कुकी और नगा मिलिशिया तीन समुदाय रहते है। मैतेई समुदाय की संख्या 53% और कुकी समुदाय 43% और शेष अन्य है। मणिपुर की 60 सदस्यों की विधानसभा में से 40 सीटों पर मैतेई समुदाय का कब्जा है। मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह भी मैतेई है। अधिकांश में यह लोग हिन्दू हैं और मणिपुर के मैदानी इलाकों में रहते हैं। जबकि कुकी पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। कुकी समुदाय को एस.टी. का दर्जा हासिल है। संविधान की धारा 371 (C) के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिये विधानसभा में इनके सदस्यों की एक कमेटी गठित की जाती है जो यहां के विकास को देखती है और सीधे राज्यपाल के नियंत्रण में होती है। पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिये धन का प्रावधान भी अलग से रहता है। इसकी रिपोर्ट सीधे राष्ट्रपति को जाती है। संविधान के अनुसार ***Manipur, which has become a State under North-Eastern Areas (reorganisation) Act, 1971, shall have a committee in its Legislative Assembly, to look after the interests of the Hill Areas in the State.*** अब मैतेई समुदाय के लोग भी कुकीयों की तर्ज पर अपने लिये एस. टी. का दर्जा दिये जाने की मांग कर रहे हैं। यह मांग ही दोनों समुदाय में झगड़े का कारण बनी हुई है।

कुकी अधिकांश में ईसाई और मैतेई हिन्दू हैं और बहुमत में हैं। मैतेई इम्फाल घाटी के मैदानी क्षेत्र में रहते हैं। कुकी समुदाय को लगता है कि यदि मैतेई समुदाय को भी एस.टी. का दर्जा दे दिया जाता है तो उनका हर चीज में दखल बढ़ जायेगा। मई में हिंसा फैलने से पहले एक अफवाह फैली कि कुकी मिलिशिया मैन द्वारा एक महिला के साथ दुष्कर्म किया गया है। इस फर्जी रिपोर्ट के बाद भड़की हिंसा अब तक रुकने का नाम नहीं ले रही है। मणिपुर में भाजपा की सरकार है लेकिन यह सरकार हिंसा रोकने में असफल रह रही हैं। केन्द्र सरकार वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने से हिचकचा रही है। यह माना जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगाकर ही हालात पर नियन्त्रण पाया जा सकता है। मैतेई समुदाय की मांग संविधान के अनुसार यदि मानी जा सकती है तो प्रदेश और केन्द्र में दोनों जगह भाजपा की सरकारें होने से इसे क्यों नहीं माना जा रहा है? यदि यह मांग संविधान सम्मत नहीं है तो प्रदेश सरकार अपने लोगों को समझा क्यों नहीं पा रही हैं। आज यह मुद्दा अंतरराष्ट्रीय आकार लेने लगा है। अमेरिका की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आ चुकी है। ऐसे में यदि राष्ट्रपति शासन लगा कर हिंसा को रोका जा सकता है तो तुरन्त प्रभाव से ऐसा कर दिया जाना चाहिये। मणिपुर की जिम्मेदारी से बंगाल और राजस्थान का नाम लेकर नहीं बचा जा सकता।

मणिपुर की हिंसा को सांप्रदायिक रंग देना गलत

गौतम चौधरी

विगत चार मई को मणिपुर में हिंसा भड़कने के बाद, इम्फाल घाटी के पहाड़ियों पर स्थित मैतई समुदाय के कई एतिहासिक मंदिरों को आग के हवाले कर दिया गया है। इसके बाद असामाजिक तत्वों ने कई गिरिजा घरों में तोड़-फोड़ किये। खबर है कि कुछ चर्चो को जला भी दिया गया है। इधर दो दिन से एक खास समुदाय विशेष की महिला को नंगा घुमाये जाने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो को लेकर लगभग सभी जिम्मेदार संगठनों ने भर्त्सना की है। यहां यह स्पष्ट कर देना ठीक रहेगा कि मणिपुर का संकट दो जातीय समूहों के बीच की लड़ाई है, न कि साम्प्रदायिक संघर्ष। इस मामले को जो लोग साम्प्रदायिक रंग देने पर तुले हैं उनके पूर्वाग्रह को साफ तौर पर देखा व समझा जा सकता है। सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रकार की एजेंसियों ने भी यह माना है कि पिछले कुछ दिनों में 100 से अधिक लोगों की जान लेने वाला मणिपुर का संकट दो जातीय समूहों के बीच की लड़ाई है। ये दोनों जातियां एक राज्य की राजधानी इम्फाल घाटी में बसी है, तो दूसरे का निवास पहाड़ियों में अवस्थित है।

देश के कुछ इसाई संगठन, राष्ट्र विरोधी ताकतें और साम्प्रदायिक तत्व इस घटना को विशुद्ध साम्प्रदायिक घोषित करने पर तुले हुये हैं। इसे हिन्दू और ईसाई समूहों की लड़ाई साबित करने की कोशिश हो रही है। बताया जा रहा है कि मैतई हिन्दू हैं और कुकी ईसाई। इसलिए इन दोनों के बीच की यह लड़ाई, हिन्दू बनाम ईसाई के बीच की लड़ाई है, जबकि तथ्य इसके ठीक विपरीत है। शेष देश के अधिकांश समाचार माध्यमकर्मी और बुद्धिजीवी पूर्वोत्तर के बारे में अनजान हैं। वे अंजाने में इस क्षेत्र की जटिलताओं को एक ऐसे विश्व दृष्टिकोण में बदलने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिसका वास्तविकता से कोई लेनादेना नहीं है। मणिपुर हिंसा के मद्देनजर गौरतलब यह है कि मैतई समुदाय के अंतर्गत ईसाई अनुयायी भी आते हैं। मणिपुर की हिंसा का प्रारंभ एक कुकी बाहुल्य जिले चुराचांदपुर से हुआ है। जो धीरे-धीरे राज्य के कई जिलों में फैल गया है। याद रहे चुराचांदपुर में मैतई समुदाय के लोगों की संख्या बहुत कम है। इस हिंसा से कुकी और मैतई दोनों समुदायों के लोग समान रूप से प्रभावित हुए हैं। सरकार ने अपने राहत शिविर, पुनर्वास और पुनर्स्थापना के तमाम प्रयास न केवल मैतई क्षेत्रों में किये हैं बल्कि कुकी बाहुल्य क्षेत्रों में भी समान रूप से किया है। देश की मीडिया का एक हिस्सा और पूर्वोत्तर ईसाई चर्चो के प्रमुख इस बात को प्रचारित करने में लगे हैं कि इस पूरी घटना में ईसाइयों को धार्मिक आधार पर उत्पीड़न किया जा रहा है। यदि ऐसा ही होता तो मैतई में जो ईसाई हैं उन्हें मैतई हिन्दुओं के द्वारा उत्पीड़ित किया जाना चाहिए था लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। उपरोक्त तथ्यों से ईसाई उत्पीड़न और धार्मिक आधार पर होने वाली हिंसा का खंडन होता है।

जहां तक सरकारी सुविधा और संरक्षण की बात है तो वह दोनों समुदायों को समान रूप से पहुंचाया जा रहा है। सरकार पर पूर्वाग्रही होने का आरोप भी निराधार साबित हो रहा है। यहां सरकारी एजेंसियां न तो जाति देख रही है और न ही संप्रदाय। मणिपुर में इस घटना के दौरान हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। समस्या अभी भी समाप्त नहीं हुई है और वह जटिल होती जा रही है। इसलिये सरकार की एजेंसी पर आरोप लगाना और इसे सांप्रदायिक रंग देना, देना देश हित के खिलाफ है। जो लोग हिंसा का शिकार हो रहे हैं, उनके लिए धर्म की पहचान कोई मायने नहीं रखता है। वे केवल और केवल हिंसा के शिकार हैं और उन्हें किसी भी कीमत पर सुरक्षा एवं सहयोग मिलना चाहिए। यहां एक बात का जिक्र करना जरूरी है कि दोनों समुदायों में वहीं सबसे ज्यादा पीड़ित हैं, जिनकी आर्थिक और सामाजिक स्थति कमजोर है। जो लोग बार-बार यह टिप्पणी दुहराते हैं कि मणिपुर की हिंसा हिन्दू मैतई और ईसाई कुकियों के बीच है वे निहायत गलत हैं। इस मामले को साम्प्रदायिक रंग देना पूरी तरह से गलत है। इससे किसी का भला होने वाला नहीं है।

जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों द्वारा मणिपुर में हिंसा की गलत व्याख्या, ठीक नहीं हैं। उन्हें इससे बचना चाहिए। यह शांति की दिशा में हो रहे प्रयास को क्षति पहुंचाने वाला साबित होगा। ऐसा करने से या केवल एक समुदाय के पक्ष में खड़े रहने से, दूसरे समुमदाय के खिलाफ पूर्वाग्रह के आरोपों को बल मिलेगा। यूनाइटेड किश्चन फोरम ऑफ नौर्थइस्ट, बैपटिस्ट चर्च कौंसिल नागालैंड, खासी जयंतिया चर्च लीडर्स फोरम और केरल के मलआमकार मार्थोमाा सीरियन चर्च के जिम्मेदार धर्माधिकारियों ने मानव जीवन के मूल्यों की रक्षा के साथ-साथ हिंसा से बचने और शांति की अपील की है। ईसाई समुदाय को यह समझना होगा कि मणिपुर की हिंसा दो नृजातीय समुहों के बीच है, ना कि किसी धार्मिक समूहों के बीच। कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें, कुछ चर्च के धर्माधिकारी और मीडिया का एक खास हिस्सा इसे साम्प्रदायिक रंग देने में लगा है। इसे किसी कीमत पर सही नहीं ठहराया जा सकता है। फिलहाल जरूरत, नफरत फैलाने के बजाये हमें अपना ध्यान विस्थापित लोगों के पुनर्वास और शांति के संदेशों पर केन्द्रित करना चाहिए, जिसका संदेश प्रभु यीशु ने समस्त मानव जाति के लिए दिया है।

शिमला स्मार्ट सिटी के स्मार्ट खेल

– एस.आर.हरनोट –

शिमला जब से स्मार्ट होना शुरू हुआ उसके हालात रामलीला के राम जैसे हो गये हैं। (इसे भगवान राम से बिलकुल न जोड़ें) रामलीला में जब किसी कलाकार को भारी भरकम मेकअप से सजाते संवारते हैं तो सब उसकी जय जय कार राम समझ कर करने लगते हैं और उस किरदार का जैसे ही मेकअप उतरा कोई नमस्ते करके भी राजी नहीं। स्मार्ट सिटी के नाम पर शिमला को भी वैसे ही तरह तरह के मेकअप से स्मार्ट बनाया गया और बनाया जा रहा है और अब धीरे धीरे उसका मेकअप भी उतरने लगा लगता है। यहां तक कि मॉल पर स्मार्ट सिटी का जो फ्लैक्स लगाया गया वह आधा फट गया है। अब उसमें स्मार्ट ही लिखा रह गया, सिटी गायब। फटे हुये फ्लैक्स में से बंदर जरूर मॉल पर चलते लोगों पर हंसते रहते हैं।

रास्तों से बात आगे बढ़ाते हैं। शिमला रिज से उच्च अध्ययन संस्थान शिमला तक हेरिटेज जॉन है। सबसे सुन्दर पैदल चलने का रास्ता। पर अब उस पर पैदल तो दूर आप गाड़ी में घंटों जाम में फंसे रह सकते हैं। कार्ट रोड से भी बदतर बना दिया है उसको। पता नहीं किन स्मार्ट लोगों की सलाह पर ये सड़क सार्वजनिक वाहनों के लिये खोल दी गई थी। दूसरा सुन्दर रास्ता शिमला रिज से संजौली का था जहां कभी इक्का दुक्का एम्बुलेंस दिखती थी। आज पूरे चार किलोमीटर के रास्ते के दोनों तरफ पार्किंग बन गई। गाड़ियों बसों की खूब आवाजाही और वहां भी अब जाम। पैदल चलना दूभर।

स्मार्ट बात यह कि इस पूरी सड़क के किनारे आम लोगों के लिये जो रेलिंग रास्ता बनाया है उस पर वर्षा से बचने के लिए छत डाल दी जो अभी भी बीच बीच में पूरी नहीं हुई। करोड़ों की इंवेस्टमेंट और लाखों टन लोहा। क्या स्मार्ट सोच थी किसी राजनेता, अफसर या इंजिनियर की.... छत लगा कर कितने बचोगे बारिश से....? घर बाजार तो बिना छत ही जाना पड़ेगा....क्या बढ़िया होता नगर निगम प्रवेश गेट पर जहां छत खत्म होती है, हजार दो हजार छाते भी रखवा देती....?

इस स्मार्ट सिटी की जन सुलभ सुविधाएं कमाल की है। मॉल रोड पर एक मात्र सुलभ शौचालय को जब से स्मार्ट बनाया वह हर महीने ऊंघता रहता है और मुरम्मत के लिये बंद। सफाई के नाम पर जीरो। अब अनाज ढाबे के पास जब आप लोअर बाजार को जाते हैं तो मात्र एक शौचालय। उसकी हालत देखकर खुद स्मार्ट हो जायेंगे....फोटो देखलीजिए, नाड़े से सीट बांध रखी है। इससे स्मार्ट आइडिया भला क्या होगा...?

पिछले पांच सालों में रेलिंग, फ्लाई पुल पर जितना लोहा लगाया गया उसने कंक्रीट से सिटी की पदोन्नति लोहे के जंगल में कर दी। कई जगह दस फीट सड़क क्रॉस करने के लिए फ्लाई पुल इतने ऊंचे बना दिए जिस पर आदमी तो क्या बंदर भी चलना पसंद नहीं करते। कभी संजौली चौक और निचली खलिनी के पुल देख लीजिए। कितने जगह जगह और। कुछ रेन शैल्टर उन जगहों पर बना दिए गए जहां कोई बस स्टॉपेज नहीं। बस कुत्तों की पौ बारह हो गई। कुछ भिखारियों ने कब्जा लिये।

छोटा शिमला में पिछले पांच दस सालों में कोई शौचालय नहीं। सभी सचिवालय रिसेप्शन में आनंद लेते हैं या पास बनाकर भीतर जा कर। छोटा शिमला गुरुद्वारे के पास से मंदिर के पीछे से जब आप नीचे जाते हैं तो वहां पिछले पांच सालों में ड्रमों के पतरों का एक वाशरूम जरूर बना जो हवा से भी हिलता रहता था। बेचारी कोई भी महिला भीतर तभी जा सकती जब बाहर पति देव दरवाजे को पकड़े रखे। भयानक मंजर है वहां। इतने बड़े स्मार्ट शहर में अभी तक उपनगरों में कोई ढंग के शौचालय नहीं।

स्मार्ट सिटी में जो स्मार्ट डंगे लगे उनमें आधे उद्घाटन के तुरन्त बाद सांसे तोड़ गए।

पानी की स्थिति तो कभी सुधरेगी नहीं। बारिश हुई के टैंक, प्लांट, पाइप सब गादों से मालोमाल।

एक जबरदस्त स्मार्ट खेल करोड़ों के सीमेंट गमलों का हुआ। दीवारों जंगलों तक सड़क के किनारे उन्हें सजाया फंसाया गया...तर्क बढ़िया कि उनमें लगे पौधे बंदर नहीं खायेंगे। शिमला पहले ही कंक्रीट और लोहे का जंगल बना दिया और ऊपर से देवदारों के बीच कई हजार गमले ठूंस दिये। यह याद पिछली सरकार के अफसरों को नहीं रही कि फूलों को पानी भी चाहिए। आज कई जगह असंख्य गमले टूट चुके हैं जिनकी इज्जत प्रतीत जंगली घास ने ढक कर बचाई है। कइयों के पेट फूल चुके और करोड़ों बरबाद। नई सरकार ने कुछ जगह जरूर पानी का प्रावधान कर लिया है जिनमें फूल जरूर खिले हैं।

गंदगी का कोई हल नहीं। न मॉल रोड की हेरिटेज गरिमा का। ऊपर से सब साफ। माल या कहीं भी रेलिंग से किसी गली में झांक लो, कचरे के ढेर दिख जायेंगे। सड़कें जो चौड़ी हो रही उतनी ही संकरी भी। अब जहां थोड़ी चौड़ाई मिली वहीं गाडियां पार्क। जाम के हाल तो मत पूछो और न सड़कों बाजारों में बैठे तहबाजारियों के। उस में भी स्मार्ट खेल.....स्थानीय या हिमाचल का कोई नहीं। बस कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक। न लिफ्ट बची, न कोई सड़क और न पुल। एक जबरदस्त काम निगम ने पिछली सरकार के रहते और किया...मॉल रिज पर लंगर, जलेबी, चने भटूरे, चाय, पकौड़ों की दुकानें सजा दी। शिमला के व्यापारी स्तब्ध। हेरिटेज जॉन की एक गरिमा होती है, वह भी ध्वस्त। शिमला मॉल अब पूरी तरह चांदनी चौक हो गया है। दाएं बाएं के नियम समाप्त। कहीं भी कोई भीख मांग रहा, चाय बेच रहा, जो खा रहा उसका कचरा शहरवासियों के सिर पर। उस पर स्मार्ट कुत्तों की सैर....जगह जगह गंदगी के ढेर। स्ट्रीट डॉग बेचारे चिल्लाते रहे, पर वे उन्हीं के मुंह पर 'हल्के' हो कर शान से चल देते हैं।

कितने खेल गिनाए जाएं स्मार्ट सिटी के.... जो कुछ अच्छा हुआ भी वह भी इस स्मार्ट खेल में छुप गया।

ये दर्द शिमला वासियों के हैं और रहेंगे। आप बर्फ गिरने का इंतजार करो.....वह शिमला से रूठ गई है....शिमला की पहाड़ियां, शिमला के देवदार, शिमला के रास्ते कंक्रीट, लोहे से ज्यादा पीडब्ल्यूडी, पर्यटन, अभियंताओं और स्मार्ट अफसरों से डरे सहमें हुए रहने लगे हैं.....अब धमाके भी जुड़ गये हैं। हम शिमला को श्यामला से पूरी तरह छीन चुके हैं....बचे हुए कुछ देवदार और सौ सौ साल पुराने अंग्रेजों के वक्त के डंगे, कुछ पुरानी इमारतें शिमला की स्मार्टनेस पर कहराते हैं पर बारूद के ढेर पर बैठे शहर के न लोग सुनते हैं न हुकुमरान। प्रकृति आहत है...दिनों दिन क्रूर होती जा रही है....कभी उसका क्रोध ना बरस पड़े..... आओ मिल कर प्रार्थना करते हैं। जय श्रीराम।

टेली-मानस पर दो लाख से अधिक कॉल्स मिली

शिमला। नेशनल टेली मेडीसिन हेल्थ प्रोग्राम (टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स: टेली-मानस 'जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम' का डिजिटल प्रारूप) की शुरूआत सरकार ने अक्तूबर 2022 में की थी, ताकि देश में मानसिक स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता को मजबूत किया जा सके। अब यह पहल एक अहम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। टोल-फ्री सेवा को इस कार्यक्रम की शुरूआत के बाद से अब तक देश के विभिन्न हिस्सों से दो लाख से अधिक कॉल्स मिली हैं। इससे पता चलता है कि इसके काम में निरंतर प्रगति हो रही है। तीन माह के मामूली से अंतराल में कॉल्स करने की संख्या में बेहद बढ़ौतरी दर्ज की गई। इस दौरान कॉल्स की संख्या एक लाख (अप्रैल 2023 में) से बढ़कर दो लाख जा पहुंची।

इस उपलब्धि के लिये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने एक ट्वीट के जरिये देशवासियों को बधाई दी है।

31 राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में टेली-मानस के 42 से अधिक प्रकोष्ठ कार्यरत हैं। प्रकोष्ठ प्रति दिन 20 भाषाओं में 1,300 से अधिक फोन करने वालों को सेवायें दे रहे हैं। उल्लेखनीय है कि 1900 से अधिक काउंसलरों को प्रशिक्षित किया गया है, जो प्रथम पंक्ति की सेवायें प्रदान कर रहे हैं। सबसे आम शिकायतों में अवसाद, अनिद्रा, दबाव और तनाव शामिल हैं। काउंसलरों ने लगभग सात हजार लोगों को दोबारा फोन करके उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली है। ये वे लोग थे, जिन्हें सेवायें देने में काउंसलरों को सफलता मिली थी। जिन फोन करने वाले लोगों को विशेष देखभाल की जरूरत थी, उन्हें डीएमएचपी और अन्य निकटवर्ती स्वास्थ सुविधा केंद्रों के साथ सफलतापूर्वक जोड़ा गया।

परीक्षाओं के दौरान परीक्षा संबंधी तनाव से जुड़ी कॉल्स में तेजी देखी गई है। काउंसलरों ने इन फोन करने वालों की मदद की। उन्हें मददगार परामर्श दिया और यह भी बताया कि कैसे खुद अपनी सहायता की जा सकती है। इस तरह उन सभी फोन करने वालों की सहायता करने में वे सफल हुये। विभिन्न शिक्षण संस्थानों में ज्यादा से ज्यादा छात्रों/किशोरों तक पहुंच बनाने की कोशिशें की जा रही हैं।

विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों, जैसे प्रिंट मीडिया, रेडियो और सोशल मीडिया के जरिये टेली-मानस सेवाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। टेली-मानस कॉलर्स को बुनियादी सलाह और मानसिक स्वास्थ्य सेवायें देता रहेगा। यह काम मौजूदा महत्त्वपूर्ण सेवाओं और संसाधनों के साथ जोड़कर किया जायेगा। आने वाले दिनों में ई-संजीवनी के साथ भी सभी सेवाओं को जोड़ दिया जायेगा। उल्लेखनीय है कि टेली-मानस की पहुंच नौ महीनों में दो लाख लोगों तक हो गई है। टेली-मानस ने देशभर में एक समग्र डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली बनाने और जहां तक उसकी पहुंच नहीं है, वहां तक अपनी पहुंच बनाने का लक्ष्य लेकर अपना सफर शुरू किया है।

टेली-मानस पहल की घोषणा केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने केंद्रीय बजट 2022-23 में की थी। घोषणा करते वक्त देश में मानसिक स्वास्थ्य संकट को ध्यान में रखा गया था। यह लोगों को सक्षम बनाने की एक अनोखी पहल है, ताकि वे अपने मानसिक स्वास्थ्य सम्बंधी मुद्दों पर सहायता प्राप्त कर सकें। इस दौरान फोन करने वालों की पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाती है। इसलिये आमतौर पर मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों को जिस हेय दृष्टि से देखा जाता है, पहचान गुप्त होने के कारण उससे बचाव हो जाता है।

नेशनल टेली मेडीसिन हेल्थ प्रोग्राम ऑफ इंडिया क्षमता निर्माण पहलों के जरिये देश में मानसिक स्वास्थ्य कार्यबल तैयार करने पर ध्यान दे रहा है। साथ ही वह यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य सेवायें हर घर और हर व्यक्ति तक निशुल्क पहुंचें। इसके तहत समाज के सबसे ज्यादा संवेदनशील और बिना पहुंच वाले लोगों तक पहुंच बनानी है। ये ऐसे लोग हैं, जिन तक अगर पहुंच नहीं बनाई गई, तो उनकी देखभाल नहीं की जा सकेगी। टेली-मानस छह महीनों में एक लाख के अहम पड़ाव तक पहुंच गई है, और इस तरह वह देशभर में एक बेहतरीन डिजिटल मानसिक स्वास्थ्य प्रणाली बनाने के लक्ष्य के नये मोड़ पर आ गई है।

टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर: 14416 या 1-800-891-4416 कई भाषाओं में है और इसके माध्यम से फोन करने वाले अपनी पसंद की भाषा चुनकर सेवायें ले सकते हैं।

प्रदेशवासियों और सरकार के सामंजस्य से बचाव एवं राहत कार्यों में हासिल हुई आशातीत सफलता

सामूहिक प्रयासों व उदारता से आपदा राहत कोष में अंशदान 16.50 करोड़ के पार

शिमला। जुलाई के शुरूआत में आये प्रकृति के प्रकोप ने हिमाचल प्रदेश से शुरू होकर धीरे-धीरे पूरे देश को आगोश में भर लिया, परंतु भारी बारिश, भू-स्खलन और बाढ़ के कारण जितना खौफनाक मंजर हिमाचल ने देखा शायद ही किसी अन्य राज्य ने देखा हो। फिर भी, इस संकट का सामना करने में प्रदेशवासियों और राज्य सरकार ने मिलकर प्रदेश के मार्गदर्शक सिद्धांत 'अतिथि देवो भव' का उदाहरण प्रस्तुत किया। अपने गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए विख्यात हिमाचल प्रदेश के लोगों और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वयं पर्यटकों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा और उनके पुनर्वास की बड़ी जिम्मेदारी ली है। इस आपदा के समय में यह प्रयास उल्लेखनीय समर्पण और निःस्वार्थता का प्रतीक बने हैं।

यह प्राकृतिक आपदा दशकों में सबसे गंभीर परिणाम लायी है जबकि राज्य की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण बचाव एवं राहत कार्य चुनौतीपूर्ण रहे हैं। इसके चलते प्रदेश के लोगों का साहस और राज्य सरकार की दक्षता दोनों का परीक्षण हुआ है। सरकार ने स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए जिम्मेदारी के साथ पहले दिन से ही विभिन्न स्थानों में फंसे हुए लोगों को सकुशल निकालने के लिए अथक प्रयास आरम्भ किये। बचाव कार्यों के सफलता से पूरा होने तक मुख्यमंत्री दिन-रात मंत्रिमण्डल सहयोगियों और अधिकारियों के साथ बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव कार्यों की निगरानी कर रहे थे।

प्रदेशवासियों और सरकार के सामंजस्य और त्वरित प्रतिक्रिया से बचाव एवं राहत कार्यों में आशातीत सफलता हासिल हुई है। आपदा राहत प्रबंधों को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने हिमाचल प्रदेश आपदा राहत कोष-2023 की स्थापना 16 जुलाई, 2023 को की गई। यह राहत कोष भारी बारिश से हुए नुकसान के पश्चात अब लोगों के पुनर्वास व अधोसंरचना की बहाली एवं मरम्मत कार्यों के उद्देश्य की पूर्ति को मद्देनज़र रखते हुए स्थापित किया गया है।

प्रदेशवासियों, विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं इत्यादि द्वारा 22 जुलाई 2023 तक 16.50 करोड़ रुपये से अधिक का अंशदान इस राहत कोष में प्राप्त हुआ है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सभी उपायुक्तों को राहत कार्यों के लिए 188.50 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इस संकट के समय में सामूहिक प्रयासों और उदारता ने करुणा और एकता की शक्ति को प्रदर्शित करते हुए लोगों के दुखों को बांट कर उनकी कठिनाइयों को कम करने का काम किया है।

शुरुआती आकलन के अनुसार आपदा के कारण प्रदेश को लगभग 8000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संवदेनशील सरकार का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करते हुए प्रभावित लोगों को सम्मानजनक राशि प्रदान करने का ऐतिहासिक फैसला लेते हुए वित्तीय सहायता राशि में कई गुणा वृद्धि की है तथा तत्काल सहायता के तौर पर एक-एक लाख रुपये देने की घोषणा की है। राहत राशि में की गई यह वृद्धि मानव जीवन, संपत्ति आदि की हानि और राहत श्रेणी के अंतर्गत आने वाले अन्य सभी उपशीर्षो में प्रदान की गई है।

राज्य सरकार ने क्षतिग्रस्त घरों (कच्चे और पक्के मकानों) और दुकानों को ऐसी आपदा के समय में दिए जाने वाले मुआवजे को बढ़ाकर एक लाख रुपये करके विशेष मापदंड अधिसूचित किए हैं। सामान के नुकसान के एवज में दस गुणा बढ़ोतरी कर 10,000 रुपये के स्थान पर अब एक लाख रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। मानवीय दृष्टिकोण का आदर्श स्थापित करते हुये अन्य क्षेत्रों में भी इतनी ही बढ़ोतरी की गई है।

अप्रत्याशित कठिनाईयों का सामना करते हुए राज्य के लोगों ने असाधारण बहादुरी एवं एकजुटता का प्रदर्शन किया। इस मुश्किल घड़ी में समर्थन एवं राहत के लिए लाखों हाथों का निःस्वार्थ रूप से आगे आना हमारे आपसी भाईचारे एवं संस्कारों का परिचायक है। भारी बारिश, भू-स्खलन व बादल फटने के कारण 9 जुलाई को आयी तबाही व इसके पश्चात हिमाचल प्रदेश की यात्रा एक मार्मिक अनुस्मारक के रूप में सदैव यह दर्शायेगी कि करुणा समुदायों को प्रकृति के सबसे कठोर प्रहारों के बावजूद भी सहन करने और पुनर्निर्माण करने में मदद कर सकती है।

70 करोड़ से होगा छैला–यशवंत नगर वाया नेरी पुल सड़क का सुदृढ़ीकरण:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सेब उत्पादकों को सुविधा प्रदान करने और उनकी उपज के लिए एक सुचारू परिवहन

सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भारी बारिश से आई आपदा के बाद राज्य सरकार सेब उत्पादक क्षेत्रों में सड़कों की बहाली पर ध्यान केंद्रित कर रही है ताकि बागवानों को सुचारू परिवहन सुविधा सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री ने यह बात वीरवार सायं आढ़ती संघ के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त सड़कों की शीघ्र बहाली के लिए युधस्तर पर मरम्मत कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि परिवहन संबंधी बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए, राज्य सरकार नेरी पुल के माध्यम से छैला से यशवंत नगर सड़क को मजबूत करने को प्राथमिकता दे रही है। सेब सीजन के दौरान बागवानों के सामने आने वाली किसी भी परिवहन बाधा को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि सीआरआईएफ के तहत इसके लिए 70 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की परियोजना का एक प्रस्ताव तैयार किया गया है।

उन्होंने कहा कि भंडारण सुविधाएं बढ़ाने के लिए सरकार राज्य भर में प्रमुख स्थानों पर नियंत्रित वातावरण सीए स्टोर स्थापित करने की योजना बना रही है। ये सीए स्टोर भावानगर किन्नौर, संदासू चिड़गांव, अणु जुब्बल, चौपाल शिमला, जाबली सोलन, सुंदरनगर मंडी, दत्तनगर रामपुर बुशहर और खड़ापत्थर शिमला में स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा, दिल्ली में कुंडली सीमा पर राज्य सरकार की भूमि पर एक और सीए स्टोर बनाने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार एक डिस्टिलरी स्थापित करने पर भी विचार कर रही है ताकि निम्न गुणवत्ता के सेब से भी बागवान लाभ अर्जित कर सकें। इस पहल का उद्देश्य उन सेबों का उपयोग करना है जो बाजार के ताजा उपज मानकों को पूरा नहीं कर सकते हैं। डिस्टिलरी की स्थापना से सरकार निम्न गुणवत्ता वाले बागवानी उत्पादों को मूल्यवान संसाधन के रूप में प्रसंस्कृत करेगी ताकि उत्पादकों की आय में वृद्धि हो सके।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार सेब उत्पादकों को शोषित करने के किसी भी प्रयास के खिलाफ अपने रुख पर कायम है। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद आढ़ती संघ ने बागवानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सेब तोलकर या पुरानी व्यवस्था के आधार पर खरीदने पर सहमति जताई। संघ ने बागवानों को समर्थन एवं फल खरीद में हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रदेश की प्रतिबद्धता के अनुरूप अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करने का विश्वास जताया।

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने सेतु भारतम योजना के तहत 300 करोड़ प्रदान करने का आश्वासन दिया:विक्रमादित्य सिंह

शिमला/शैल। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नई दिल्ली में केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट कर उन्हें हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, भूस्खलन और बादल फटने से राष्ट्रीय राजमार्गो को हुए नुकसान से अवगत करवाया।

उन्होंने केन्द्रीय मंत्री को प्रदेश में विभिन्न सड़कों एवं पुलों को हुये भारी नुकसान से भी अवगत करवाया। उन्होंने आग्रह किया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को क्षतिग्रस्त सड़कों एवं पुलों के बारे में दी गई नुकसान के आकलन की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय राशि शीघ्र उपलब्ध करवाई जाये।

उन्होंने पंडोह, भुंतर, कुल्लू, रायसन, कटराई और मनाली क्षेत्र के पुलों के अलावा मनाली–मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग, नालागढ़ पुल और प्रदेश लोक निर्माण विभाग के अन्य पुलों और सड़कों की शीघ्र बहाली और मरम्मत करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि यातायात को सुचारू करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गो को जोड़ने वाली सड़कों एवं पुलों तथा चक्की पठानकोट पुल को तत्काल बहाल करने और मरम्मत की आवश्यकता है।

लोक निर्माण मंत्री ने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्गो को जोड़ने वाले राज्य लोक निर्माण विभाग के क्षतिग्रस्त पुलों के पुनर्निर्माण के लिए सेतु भारतम योजना के तहत 300 करोड़ रुपये प्रदान करने का आश्वासन दिया है। केन्द्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्गो पर भूस्खलन संभावित क्षेत्रों पर ब्लैक स्पॉट की पहचान कर समस्या का स्थायी समाधान करने के भी निर्देश दिए।

उन्होंने राज्य लोक निर्माण विभाग के पुलों की बहाली एवं मरम्मत के लिए धन उपलब्ध करवाने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए ताकि राज्य लोक निर्माण विभाग की सड़कों को वैकल्पिक सड़कों के रूप में राष्ट्रीय राजमार्गो से जोड़ा जा सके।

बैठक में मंडी से सांसद प्रतिभा सिंह भी उपस्थित थीं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को अपने संसदीय क्षेत्र की सड़कों की स्थिति से अवगत करवाया और उदारता से सहायता प्रदान करने का आग्रह किया।

उद्योग विभाग रणनीतिक निवेश योजना तैयार करने के लिए प्रतिबध:हर्षवर्धन चौहान

शिमला/शैल। राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्रों में आशातीत बदलाव लाने के लिए मुख्यमंत्री, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दृष्टिकोण के लिए आभार व्यक्त करते हुए उद्योग मंत्री, हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि विश्व बैंक और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एमओएमएसएमई की सहायता से भारत सरकार की एक प्रमुख योजना, राइजिंग एंड एक्सेलेरेटिंग एमएसएमई परफारमेंस आरएएमपी कार्यक्रम की शुरुआत के लिए प्रदेश में सार्थक प्रयास आरंभ कर दिए गए हैं।

उद्योग मंत्री, हर्षवर्धन चौहान के निर्देश पर अर्नस्ट एंड यंग कंपनी को रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी की तैयारी के लिए बोली प्रक्रिया के माध्यम से परामर्श एजेंसी के रूप में चयनित किया गया है। उन्होंने कहा कि एजेंसी ने एसआईपी तैयार करने का कार्य आरंभ कर दिया है और राज्य में क्लस्टर विकास कार्यक्रम में भी सहायता कर रही है। एजेंसी ने सिरमौर जिले के काला अंब और पावंटा साहिब में उद्योग हितधारकों के साथ संवाद किया।

संवाद के दौरान सामने आए विभिन्न पहलू हिमाचल में रैम्प योजना आरएएमपी कार्यक्रम की विशिष्ट आवश्यकताओं और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तैयार रणनीतिक निवेश योजना को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मंजूरी मिलने के उपरांत एसआईपी वित्त, बाजार, प्रौद्योगिकी, क्षमता निर्माण और अन्य आवश्यक समर्थन तक पहुंच के माध्यम से एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगा। एसआईपी को अगले चार वर्षो में राज्य एमएसएमई और उद्योग संघों के माध्यम से सक्रिय रूप से लागू किया जाएगा।

परामर्श एजेंसी उद्योग की जरूरतों को पूरा करने और रैम्प योजना व क्लस्टर विकास कार्यक्रम के बारे में जागरूकता साझा करने के लिए शीघ्र ही विभिन्न जिलों में संवाद, कार्यशालाएं और केंद्रित समूह चर्चाएं आयोजित करेगी।

निदेशक उद्योग राकेश कुमार प्रजापति ने एमएसएमई और उद्योग संघों से सक्रिय रूप से इस संवाद में भाग लेने और बाजार व कृषी प्रौद्योगिकी तक पहुंच और एमएसएमई से संबंधित अपनी आवश्यकताओं और शंकाओं को साझा करने का आग्रह किया।

हिमाचल चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष सतीश कुमार गोयल और महासचिव नवीन अग्रवाल, फार्मा एसोसिएशन काला अंब के अध्यक्ष केशव सैनी और उद्योग संघों के अन्य प्रमुख सदस्य व पदाधिकारी इस संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए।

एसजेवीएन ने आपदा राहत कोष में 2.55 करोड़ रुपये का किया अंशदान

शिमला/शैल। सतलुज जल विद्युत निगम के अध्यक्ष नंद लाल शर्मा ने निगम की ओर से बाढ़ प्रभावित

परिवारों को सहायता प्रदान करने के दृष्टिगत आपदा राहत कोष–2023 के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को 2,55,00,000 रुपये की राशि के चेक प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस राशि से संकट की घड़ी में प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने में मदद मिलेगी।

मानसून सीजन में नुकसान पर मुख्य सचिव ने केन्द्रीय टीम के साथ की बैठक

शिमला/शैल। प्रदेश में इस मानसून सीजन के दौरान अभी तक हुए नुकसान का आकलन करने पहुंची केंद्र की अंतर–मंत्रलीय टीम ने मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और संबंधित विभागों के उच्च अधिकारियों से बैठक की तथा नुकसान की रिपोर्ट पर चर्चा की।

इस अवसर पर मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में हुए नुकसान का गहन आकलन किया गया है। उन्होंने राज्य के अधिकारियों से कहा कि नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट के लिए दिशा–निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुये तथ्य प्रस्तुत किये जायें। आपदा से हुये नुकसान के दृष्टिगत केन्द्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि से सहायता प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्तरों पर मामले को सही परिपेक्ष्य में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बारिश के कारण हुये नुकसान का जायजा लेने के लिये स्पेस वेस्ड एप्लीकेशन की उपयोगिता सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि राहत कार्यो के दौरान ड्रोन और आपदा मित्रों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इस अवसर पर केन्द्रीय टीम के अध्यक्ष रविनेश कुमार ने बताया कि टीम ने दो अलग–अलग समूहों में आपदा प्रभावित ज़िलों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने राहत एवं बचाव के लिए स्थानीय प्रशासन और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना भी की। रविनेश कुमार और टीम में अन्य सदस्यों ने रिपोर्ट के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए।

इस अवसर पर आपदा के दौरान विभिन्न राहत एवं बचाव कार्यो पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण भी दिया गया। यह अवगत करवाया गया कि 24 जून से 14 जुलाई, 2023 तक सामान्य से 147 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई है जबकि 7 से 11 जुलाई तक सामान्य से 436 प्रतिशत अधिक बारिश जबकि मानसून के दौरान अभी तक प्रदेश में भूस्खलन की 5480 घटनाएं, बादल फटने की 14 और "लैश "लड की 83 घटनाएं हुई हैं। इस अवसर पर राहत एवं बचाव कार्यो पर आधारित एक लघु वृतचित्र भी प्रस्तुत किया गया।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अभिषेक त्रिवेदी, प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और अंतर–मंत्रालीय टीम के सदस्य बैठक में उपस्थित थे।

अन्य राज्यों में पंजीकृत संविदा बसों की कर दरों में आंशिक संशोधन

शिमला/शैल। परिवहन विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार ने मोटर यान कराधान अधिनियम, 1972 के तहत जारी अधिसूचना के प्रावधानों में आंशिक उपांतरण किया है।

इसके तहत अखिल भारतीय पर्यटक यान परमिट नियम, 2023 के अंतर्गत नहीं आने वाली अन्य राज्यों में पंजीकृत संविदा गाड़ी बसों एवं अन्य राज्यों में पंजीकृत व हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने वाली पर्यटक परमिट से भिन्न बसों के कर में परिवर्तन किया गया है। 13 से 32 सीटों वाली साधारण सेवा, सेमी डीलक्स सेवा व डीलक्स बस सेवा के लिए कर की दर 3000 रुपये प्रतिदिन होंगी। 32 से अधिक सीटों वाली साधारण सेवा, सेमी डीलक्स सेवा व डीलक्स बस सेवा के लिए यह 4000 रुपये प्रतिदिन होगा। इनमें सीटों की क्षमता चालक को अपवर्जित छोड़कर करके होगी। वातानुकूलित बस सेवा के लिए दर 6000 रुपये प्रतिदिन निर्धारित की गई हैं।

उन्होंने बताया कि अखिल भारतीय पर्यटक यान परमिट नियम, 2023 के अंतर्गत आने वाली अन्य राज्यों में पंजीकृत संविदा गाड़ी बसों और हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने वाली 13 से 32 सीटों की क्षमता की साधारण सेवा, सेमी डीलक्स सेवा व डीलक्स सेवा के लिए कर की दरें 3000 रुपये प्रतिदिन, 15000 रुपये साप्ताहिक और 50000 रुपये मासिक होंगी। 33 से अधिक सीटों वाली साधारण सेवा, सेमी डीलक्स सेवा व डीलक्स सेवा के लिए यह दर 4000 रुपये प्रतिदिन, 20000 रुपये साप्ताहिक और 60000 रुपये मासिक होगी। यह चालक व वातानुकूलित को अपवर्जित छोड़कर करके होगा। वातानुकूलित बस सेवा के लिए कर 5000 रुपये प्रतिदिन, 25000 रुपये साप्ताहिक और 75000 रुपये मासिक निर्धारित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की 'सशक्त महिला ऋण योजना' का शुभारंभ किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की सशक्त

महिला कृषि योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत हिमाचल की स्थायी निवासी महिलाओं को अपने उद्यम स्थापित करने, आजीविका गतिविधियों को आरंभ करने, रोजमर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने तथा अपने परिवारों के उत्थान के लिए उपभोग्य सुरक्षा कोलेटरल मुद्रा प्रदान किया जाएगा।

इस अवसर पर, मुख्यमंत्री ने इस पहल के लिए बैंक के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह सुविधा प्रदान कर बैंक ने प्रदेश की महिलाओं को सशक्त करने तथा उन्हें कठिन समय में पुनर्भुगतान न कर पाने की स्थिति में अपनी संपत्ति खोने के डर से मुक्त किया है।

उन्होंने कहा कि उपभोग्य सुरक्षा मुक्ति इस योजना की अनूठी विशेषता है और इसके तहत ऋण के लिए आवेदन करने वाली पात्र महिलाओं को ऋण राशि के विरूध जमानत के रूप में कोई संपत्ति या संपार्श्विक प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि उपभोग्य सुरक्षा की शर्त हटाने से महिलाओं विशेषकर जिनके पास ऋण लेने के लिए जमानत के रूप में मूल्यवान संपत्ति नहीं होती है, उनकी मुख्य बाधा दूर होगी।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि महिलाओं को स्वरोजगार और आजीविका गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर यह योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में योगदान देगी और उन्हें वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनने और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में सहायक सिध होगी।

उन्होंने कहा कि योजना के तहत बैंक 8.51 प्रतिशत की कम ब्याज़ दर पर 21000, 51000 तथा 1,01000 रुपये की ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है। इसके अलावा यह योजना पात्र महिलाओं को आसानी से ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। योजना में मार्जिन मनी की आवश्यकता नहीं है और आवेदन प्रक्रिया भी सरल है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बैंक की इस नई पहल के माध्यम से ऋणी महिलाएं आत्मविश्वासी व आत्मनिर्भर बनेंगी और राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास में सार्थक योगदान देंगी। उन्होंने कहा कि यह योजना समय पर पुनर्भुगतान करने पर पुरस्कृत करने और ऋणी महिलाओं को समय पर ऋण राशि चुकाने के लिए प्रोत्साहित करने पर भी केंद्रित है।

इस अवसर पर बैंक के अध्यक्ष देवेन्द्र श्याम, मुख्यमंत्री के ओएसडी रितेश कपरेट, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, बैंक के प्रबंध निदेशक शरवन मांटा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

'एक राज्य-एक पोर्टल' प्रणाली से आनलाईन उपलब्ध होंगी शहरी निकायों की सभी सेवाएं मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी शहरी स्थानीय निकायों में विभिन्न नागरिक सेवाएं आनलाइन उपलब्ध करवाने की सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत 'एक राज्य-एक पोर्टल' प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए हैं। शहरी विकास विभाग की यहां आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने यह बात कहीं।

उन्होंने सभी सरकारी सेवाओं को आनलाइन करने पर भी बल दिया ताकि लोगों को कार्यालयों के बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें।

उन्होंने सम्पत्ति कर, बिलों का भुगतान, नोटिस प्रबन्धन, सभी अनापत्ति प्रमाणपत्र और स्वीकृतियों इत्यादि को आनलाइन करने के निर्देश दिए। इससे लोगों को तत्काल सेवाएं उपलब्ध होंगी और भ्रष्टाचार की संभावनाएं भी न्यून होंगी। उन्होंने कहा कि सभी शहरी स्थानीय निकायों में सम्पत्ति कर की गणना और एकत्रिकरण भी आनलाइन माध्यम से किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इनके संचालन को और अधिक सुव्यवस्थित बनाने के लिए, राज्य के सभी 61 स्थानीय शहरी निकायों, 35 अधिसूचित विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण साडा तथा 56 योजना क्षेत्रों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी और गवर्नेंस विभाग की सहायता से एक पूर्ण स्वचालित आनलाइन भवन अनुमति प्रणाली विकसित की जा रही है। यह प्रणाली स्वत: छंटनी सुविधाओं के माध्यम से नए भवन चित्रें की वास्तविक समय में जांच करने में सक्षम होगी, जिससे अनुमोदन प्रक्रिया में दक्षता और सटीकता सुनिश्चित हो सकेगी।

उन्होंने कहा कि नई प्रणाली में आवेदनों और दस्तावेजों को अपलोड करने की भी सुविधा उपलब्ध होगी और इसके माध्यम से अनुमतियां और नोटिस इत्यादि जारी किए जा सकेंगे। उन्होंने बार-बार आपत्तियां इंगित करने की प्रथा बंद करते हुए केवल एक बार ही सभी आपत्तियों का उल्लेख करने पर भी बल दिया। उन्होंने शहरी स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली को और आधुनिक बनाने तथा लेखा संबंधी रिकार्ड के लिए डिजिटल तकनीक अपनाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक के समावेश से शहरी स्थानीय निकायों और सरकारी विभागों में सेवाओं को सुव्यवस्थित किया जा सकेगा, जो कुशल प्रशासन प्रदान करने और नागरिक केंद्रित सेवाओं के प्रति प्रदेश सरकार की प्रतिबधता को दर्शाता है।

बैठक के दौरान ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला नगर निगम में जल आपूर्ति की अद्यतन स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने गाद और बाढ़ से प्रभावित जल आपूर्ति योजनाओं की बहाली के लिए तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने सिल्ट की समस्या के समाधान के लिए गिरि नदी पर बांध बनाने और इस बांध का डिजाइन ऊर्जा निगम द्वारा तैयार करने की भी बात कही। इसके अलावा, उन्होंने सेओग में 9 एमएलडी क्षमता के जल भंडारण टैंक की मुरम्मत करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि इससे शिमला शहर में जलापूर्ति की समस्या काफी हद तक दूर हो सकेगी।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी एवं नवाचार गोकुल बुटेल, महापौर, शिमला नगर निगम सुरेंद्र चौहान, उप महापौर उमा कौशल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, प्रधान सचिव शहरी विकास देवेश कुमार, सचिव सूचना प्रौद्योगिकी ड . अभिषेक जैन, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव विवेक भाटिया, निदेशक शहरी विकास कमल कांत सरोच, निदेशक डिजिटल टेक्नोलाजी एवं गवर्नेंस मुकेश रेपसवाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सामान्य भविष्य निधि अभिदाताओं की वार्षिक विवरणियां वेबसाइट पर उपलब्ध

शिमला/शैल। प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हिमाचल प्रदेश के प्रवक्ता ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार के सामान्य भविष्य निधि अभिदाताओं को वर्ष 2022-23 की वार्षिक विवरणियां आहरण एवं सवितरण अधिकारी डीडीओ द्वारा डाउनलोड करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की वेबसाइट www.himkosh.nic.in पर उपलब्ध करवा दी गई हैं।

उन्होंने कहा कि इस वेबसाइट पर सामान्य भविष्य निधि जीपीएफ विवरणियों के लिंक पर क्लिक करने के उपरांत विभिन्न निर्देशों का अनुपालन कर यह डाउनलोड की जा सकती है। उन्होंने सभी डीडीओ को उपलब्ध करवाये गये पासवर्ड को सुरक्षा के लिए बदलने का आग्रह किया। यदि किसी डीडीओ को पासवर्ड प्राप्त नहीं हुआ है तो वह दूरभाष संख्या 0177-2600279 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

उन्होंने सभी डीडीओ से अनुरोध किया कि अपने कार्यक्षेत्र में आने वाले सभी कर्मचारियों की वर्ष 2022-23 की जीपीएफ विवरणियों के बैलेंस को अपने वेतन बिल रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टि करने के उपरान्त सभी कर्मचारियों को यथाशीघ्र प्रदान करके इस कार्यालय को सूचित करें।

प्रवक्ता ने सभी सबस्क्राइबर व डीडीओ से आग्रह किया कि अपनी वार्षिक जीपीएफ विवरणियों में दर्शाये गए आंकड़ों से स्वयं को सन्तुष्ट कर लें। यदि उन्हें इसमें कोई त्रुटि लगे तो वार्षिक जीपीएफ विवरणी की प्राप्ति की तिथि से तीन माह के भीतर प्रधान महालेखाकार कार्यालय की वेबसाईट www.aghp.cag.gov.in में शिकायत एवं सुझाव दर्ज करें या agaehimachalpradesh@cag.gov.in पर ई-मेल करें। उन्होंने डीडीओ से यह भी आग्रह किया कि वर्ष 2023-24 के दौरान किसी भी कर्मचारी द्वारा लिये जाने वाले आहरण को भी इसी विवरणी के आधार पर स्वीकृत करें।

हिमाचल राज्य सहकारी बैंक ने आपदा राहत कोष के लिए दिया योगदान

शिमला। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष देवेन्द्र श्याम ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह ठाकुर को आपदा राहत कोष-2023 के लिए

बैंक की ओर से 7,06,18,702 रुपये का चेक भेंट किया।

मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस राशि से प्रभावित परिवारों को सहायता मिलेगी। समाज का हर वर्ग इस कठिन समय में मदद के लिए आगे आ रहा है, जिसके लिए राज्य सरकार उनकी आभारी है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के ओएसडी रितेश कपरेट, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, बैंक के प्रबंध निदेशक शरवन मांटा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

महापौर सहित पार्षदों ने आपदा राहत कोष के लिए प्रदान किया मानदेय

शिमला/शैल। शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान और उप-महापौर उमा कौशल सहित अन्य पार्षदों ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। राज्य में मूसलाधार

बारिश के कारण बड़े पैमाने पर हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए महापौर और उप-महापौर ने अपना एक महीने का मानदेय 'आपदा राहत कोष-2023' के लिए प्रदान किया है।

महापौर ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि नगर निगम शिमला के कई पार्षदों ने आपदा राहत कोष में योगदान देने के लिए इच्छा व्यक्त की है।

निगम के कंगनाधर वार्ड के पार्षद आर.आर.वर्मा ने मुख्यमंत्री को आपदा राहत कोष के लिए 6 लाख रुपये के चेक के रूप में अपने कार्यकाल के पांच वर्ष का मानदेय प्रदान किया।

पार्षद गीतांजलि भागड़ा ने 2 लाख रुपये, पार्षद आलोक पठानिया ने 7000 रुपये तथा पार्षद कृष्ण राम ने 5100 रुपये की राशि आपदा राहत कोष के लिए प्रदान की।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

क्या डॉ. बिंदल की टीम मैरिट का चयन है या समझौतों का

- नयी टीम में पिछला चुनाव हारे हुये नौ लोगों को पदों से नवाजा गया है
- सात ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनके खिलाफ अधिकृत प्रत्याशियों के विरुद्ध काम करने का आरोप हैं
- क्या टीम संगठन पर कब्जे का प्रयास है?

शिमला/शैल। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दावा करने वाली भाजपा जब प्रदेश विधानसभा के चुनाव हार गयी थी तब इस हार के कारणों का आकलन करके उसके परिणामों को सार्वजनिक नहीं कर पायी थी। क्योंकि उस आकलन में यह सामने आना था कि चूक पन्ना प्रमुखों और त्रिदेवों के स्तर पर हुई थी या इन्हें गढ़ने वाले उच्च देवों के स्तर पर। कारण और परिणाम जो भी रहे हों लेकिन यह स्पष्ट हो गया है कि पन्ना प्रमुखों और त्रिदेवों का प्रयोग तब तक सफल नहीं हो पायेगा जब तक सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे हुकमरान अपने को इस अवधारणा से बाहर निकालकर आम आदमी के प्रति अपनी जवाबदेही की प्रतिबद्धता पर व्यवहारिक रूप से अमल नहीं करते हैं। क्योंकि जिन लाभार्थियों को वोट बैंक का डिपॉजिट माना जा रहा था उनकी गिनती शायद इन्हीं पन्ना प्रमुखों और त्रिदेवों से शुरू होकर इन्हीं पर खत्म हो जाती है। इस त्रिदेवों की अवधारणा को पुराने कार्यकर्ताओं के स्थान पर नयों का आगे लाने के लिये प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रयोग से पुराने कार्यकर्ताओं और नयों के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी होती जा रही है जो आने वाले समय में संगठन के लिये एक बड़ी समस्या खड़ी हो जायेगी। पिछले दिनों जब संगठन मंत्री सिद्धार्थन सोलन में पार्टी टिफिन बैठक में पहुंचे तो उस बैठक में 120 लोगों में से केवल 20 ही भाजपा के सदस्य थे और शेष वह लोग थे जो पहली बार किसी बैठक में देखे गये। शायद बैठक में कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी बुला लिये गये थे। सोलन मण्डल के भी पूरे पदाधिकारी बैठक में नहीं थे। महिला मोर्चा, एससी मोर्चा, किसान मोर्चा और अन्य प्रकोष्ठों के लोगों को बैठक की सूचना तक नहीं थी। शायद बैठक में योजनाओं के लाभार्थियों को ही वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में पेश किया गया। इस बैठक से यह स्पष्ट हो गया है कि पार्टी के भीतर पुराने कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करके लाभार्थी रहे त्रिदेवों और पन्ना प्रमुखों द्वारा ही पार्टी पर कब्जा करने की कवायद शुरू हो गयी है। सोलन की इस बैठक के बाद ही प्रदेश पदाधिकारियों की सूचीयां जारी हुई है। इन सूचियों का अवलोकन करने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि शायद अध्यक्ष यह पदाधिकारियों की सेना चुनने में पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं रहे हैं। जिला अध्यक्षों से प्रदेश पदाधिकारियों की जो सूचियां जारी हुई है उनमें विभिन्न धड़ों को प्रसन्न रखने का प्रयास ज्यादा नजर आ रहा है। ऐसा लगता है कि यह मानकर यह चयन किया गया है कि हिमाचल में हर बार सत्ता तो बदल ही जाती है। इस नाते अगली बार भाजपा की बारी है इसलिये किसी न किसी तरह संगठन पर कब्जा किया जाये।

डॉ. राजीव बिंदल की टीम में युवा और महिला मोर्चा के अध्यक्षों के अतिरिक्त नौ उपाध्यक्ष तीन महामंत्री सात सचिव, दस प्रवक्ता, एक मीडिया प्रभारी और सात सह मीडिया प्रभारी हैं। यह इस टीम की जिम्मेदारी होगी कि वह कार्यकर्ताओं को आने वाले लोकसभा चुनाव और फिर विधानसभा चुनावों में जीत के लिये क्या मंत्र देते हैं। आम कार्यकर्ताओं की यह प्रतिक्रिया है कि इस टीम का चयन जे.पी. नड्डा और पवन राणा के दबाव में किया गया है। यह आरोप लग रहा है कि इस टीम में नौ लोग ऐसे हैं जो पिछले विधानसभा चुनावों में प्रत्याशी थे और खुद अपना ही चुनाव हार गये हैं। यदि यह लोग अपना चुनाव जीत गये होते तो आज प्रदेश में भाजपा की सरकार होती। छः सात पदाधिकारी ऐसे कहे जा रहे हैं जिनके अपने खिलाफ विधानसभा चुनावों में अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ काम करने के आरोप हैं। जिन पदाधिकारियों के खिलाफ पिछली बार संगठन की लुटिया डुबाने के आरोप लगते रहे उन्हें इस बार भी पदों से नवाजा गया है। यहां तक कहा जा रहा है कि संघ से आये तिलक राज शर्मा एक धीर गंभीर प्रवृति के व्यक्ति हैं। पिछली बार वह सभी मोर्चा के समन्वयक थे। उन्हें अब डिमोशन करके युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया गया है। देखने में वह प्रौढ़ लगते हैं इसलिये यह सवाल उठ रहा है कि युवा उन्हें कैसे स्वीकार कर पायेंगे।

इस तरह जो टीम डॉ. बिंदल सामने लाये हैं और उस पर संगठन के भीतर ही दबी जुबान से जो सवाल उठने लग पड़े हैं उससे यह लगता है कि यह टीम मैरिट का नहीं समझौतों का चयन ज्यादा है। आने वाले दिनों में जब यह दबी जुबान से उठ रहे सवाल पूरी मुखरता के सामने आयेंगे तो अध्यक्ष के लिये स्थितियां संभालना कठिन हो जायेगा।

शिमला धमाके की जांच के लिये पांचवे दिन पहुंची एन.एस.जी.

लोगों में फैलते भ्रम के लिए आवश्यक था एन.एस.जी का आना

शिमला/शैल। शिमला के मिडल बाजार स्थित हिमाचल रसोई रेस्तरां में 18 जुलाई शाम को 7:00 बजे हुये धमाके की जांच अब एनएसजी के पास पहुंच गयी है। इस धमाके में एक कारोबारी अवनीश सूद की मौत हो गयी थी और 13 लोग जख्मी हुये थे। धमाका इतना जोरदार था कि इसमें मिडल बाजार और माल रोड की 25 दुकानों और घरों के शीशे चटक गये थे। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस के मुताबिक यह धमाका गैस सिलैन्डर के फटने से हुआ है। लेकिन स्थल पर सबसे पहले पहुंचे फायर ऑफिसर ने वहीं से दो सिलैन्डर बाहर निकाल कर रख दिये थे। उसके मुताबिक कोई सिलैन्डर नहीं फटा था। घटनास्थल पर कोई आग भी नहीं लगी थी। परन्तु जब पुलिस अधीक्षक ने ही एक पत्रकार वार्ता में धमाके का कारण सिलैन्डर फटना बताया तो उससे एक भ्रान्ति की स्थिति बन गई। इस धमाके से जिन लोगों के आवास और दुकानें प्रभावित हुई हैं वह भी इसे सिलैण्डर फटना नहीं मान रहे हैं। पुलिस ने धारा 336, 337 और 304 (A) के तहत एफ.आई.आर दर्ज करके धमाके के कारणों की जांच शुरू कर दी है। फॉरैन्सिक टीम ने भी घटनास्थल का दौरा करके मौके से साक्ष्य जुटाकर अपनी जांच शुरू कर दी है। लेकिन अभी कोई रिपोर्ट नहीं आयी है। ऐसे में जब घटनास्थल पर कोई सिलैन्डर न फटने पर भी इसे गैस सिलैन्डर फटना कहा गया तब स्वतः ही एक भ्रांति और सन्देह का वातावरण बन गया। इस सन्देह को दूर करने के लिये स्थानीय विधायक हरीश जनारथा के आग्रह पर मुख्यमंत्री और डी.जी.पी. ने केन्द्र से आग्रह करके एन.एस.जी. को यह जांच सौंपी है। एन.एस.जी. की 16 सदस्यों की जांच टीम ने 5 दिन बाद आकर घटनास्थल का निरीक्षण करके मौके से साक्ष्य जुटाये हैं। एनएसजी ने पुलिस और फॉरैन्सिक टीम से भी मंत्रणा की है। घायलों से मिलकर उनके ब्यान भी लिये हैं। अब एन.एस.जी. की जांच रिपोर्ट आने का इन्तजार है। जब पुलिस और फॉरैन्सिक टीम की भी रिपोर्ट आ जायेगी तब तीनों जांच रिपोर्टों के बाद इस धमाके के कारणों का खुलासा हो पायेगा। लेकिन आम आदमी के मन में उठते सन्देहों के निराकरण के लिये केन्द्रीय टीम का लाया जाना आवश्यक था। इसके लिये विधायक और सरकार के प्रयासों की सराहना की जा रही है।